committee? Have they got a say in the matter?

Shri Raj Bahadur: I do not think they are represented. The State Governments, however, have a right to consult the Committee or the Board as and when needed.

N.E.S. Blocks, West Bengal

*295. **Shri S. C. Samanta:** Will the Minister of Community Development be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 363 on the 28th May, 1957 and state when the N.E.S. Blocks at Kolaghat and Pauskura in the district of Midnapur, West Bengal were officially declared opened?

The Minister for Community Development (Shri S. K. Dey): 2nd October, 1956.

Shri S. C. Samanta: May I know whether on the 2nd October, 1956, the Block officers for these blocks were appointed and they worked on?

Shri S. K. Dey: The Block officers were not appointed to these blocks till sometime in February and June 1957.

Shri S. C. Samanta: May I know whether in the place of the Block officer any other Block officer was officiating there and whether the work that was entrusted to the Block officer formerly was suffering?

Shri S. K. Dey: A Sub-divisional officer was looking after these blocks and also a Block development officer of an adjoining block. Block officers could not be appointed because of the difficulties of floods and elections following.

Shri S. C. Samanta: May I know whether the duration of three years will be calculated from 2nd October and whether the works that will suffer will be compensated afterwards if not completed?

Shri S. K. Dey: The period will be extended if the works cannot be completed.

सड़कों का विकास

*२९७ **श्री भक्त दर्शन :** क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय तथा आर्थिक महत्व की सड़कों के विकास के लिये राज्य सरकारों को विशेष अनुदान देने के उद्देश्य से १८ करोड़ रुपये की धन राशि निश्चित की गई है,

(ख) यदि हां, तो उस धनराशि का विभिन्न राज्यों में वितरण करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है, और

(ग) यदि विभिन्न राज्यों ने सड़कों के विकास के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजे हों, तो क्या उनका विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) १८ करोड़ रुपये की पूंजी का वितरण इस प्रकार दिया गया :—

१ पहली योजना में से स्वीकृत सड़क योजनाओं के लिए शेष १५ करोड़ रुपये की पूंजी को आगे के लिए नियत कर दिया गया है।

२ २ करोड़ रुपये की पूंजी को, उत्तर तथा उत्तर-पूर्वी सरहदी क्षेत्र में नई सड़क योजनाओं के लिए और १ करोड़ रुपये की पूंजी महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों में जाने वाली उन सड़कों के विकास के लिए नियत कर दी गई है जिनकी स्वीकृति दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में दी जायेगी।

विभिन्न राज्यों में सरहदी सड़कों और पर्यटक-सड़कों के लिये जो अनुदान निर्धारित

कर दिया गया है उसके वितरण का अभी तक निश्चय नहीं किया गया है ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८९]

I shall also read the answer in English. (a) Yes.

(b) The sum of Rs. 18 crores has been allocated as follows:

(1) Rs. 15 crores for approved road schemes carried over from the first plan;

(2) Rs. 2 crores for new road schemes in the north and north-eastern border region and Rs. 1 crore for the development of roads leading to or serving important tourist centres, to be approved during the second plan period.

The distribution of the provisions earmarked for the border roads and tourist roads among the various States has not yet been decided.

(c) A statement is laid on the Table of the Sabha. [*See* Appendix I, annexure No. 89].

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इन सड़कों का निर्णय करते समय राज्य सरकारों की सिफारिशों को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया जाता है या केन्द्रीय सरकार भी उन पर विचार करती है ? और क्या इस सम्बन्ध में संसद सदस्यों की सिफारिशें भी निमंत्रित की जा सकती हैं और क्या उन पर विचार किया जायेगा ?

श्री राज बहादुर : इन सड़कों के बारे में बहुधा राज्य सरकारें ही अपनी सिफारिशें देती हैं । उन पर विचित्र रूप से ध्यान दिया जाता है । मैं समझता हूं कि जो सुझाव संसद सदस्यों की ओर से आते हैं उन पर भी केन्द्रीय सरकार विचार करती है और उन पर उचित ध्यान दिया जाता है ।

श्री भक्त दर्शन : पिछली बार सड़ के लिए जब रुपया वितरित किया गया उस समय, मंत्री महोदय मुझे ऐसा कहने के लिए क्षमा करेंगे, कुछ इलाकों के साथ पक्षपात किया गया था और कुछ इलाकों को उनके उचित हिस्से से कम रुपया दिया गया । मैं उस इलाके का नाम नहीं लेना चाहता, मंत्री महोदय स्वयं जानते हैं, जैसे कि गढ़वाल का इलाका । मैं जानना चाहता हूं कि आयन्दा रुपये का वितरण करने में क्या उन इलाकों का खयाल रखा जायेगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : माननीय सदस्य ने यह कहा है कि निष्पक्षता का व्यवहार नहीं किया है । इस सम्बन्ध में पहली बात तो यह है कि हम रुपया देते हैं, और किन सड़कों पर वह रुपया लगाया जायेगा इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों पर है । हम किसी सड़क का नाम यहां से तै नहीं करते कि अमुक सड़क के लिए यह रुपया देना है या दूसरी सड़क के लिए देना है । दूसरे जो अल्मोड़ा जिले को ज्यादा रुपया मिला उसका कारण माननीय सदस्य को मालूम है कि वह एक सरहदी क्षेत्र है और वहां सरहद की सड़कें हैं । और वहां कुछ स्ट्रेटिजिक कारणों से भी ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ता है । हमें दूसरी मिनिस्ट्रियों ने भी इस बारे में कहा, इसलिए भी ज्यादा रुपया दिया गया ।

Shrimati Renuka Ray: In view of the national importance of having roads in inaccessible border areas of States such as West Bengal, what proportion does the Government of India contemplate to give to build such roads?

Shri Raj Bahadur: I have just now indicated that Rs. 2 crores have been allocated for this purpose.

Shrimati Renuka Ray: I would like to know how much has been sent to these States up till now and how much is going to be sent to West Bengal in future.

The Minister of Transport and Communications (Shri Lal Bahadur Shastri): I do not exactly remember the

figure, but I might assure the hon. Member that many demands made so far by the State Government have been met. Not all, but generally a certain precentage is given, and we have rather increased the proportion in a few instances in the case of West Bengal.

Shrimati Renuka Ray: Is the Minister aware that the West Bengal Government have said that they have not been able to get sufficient funds for the border roads and therefore they have not been able to build them?

Shri Lal Bahadur Shastri: It will be never adequate from the States' point of view. They always want more, and we try to give them as much as we can.

Shrimati Renuka Ray: From the national point of view, not the State's point of view.

श्री म० ला० द्विवेदी क्या केन्द्रीय सरकार सडके बनाने के काम मे अपना यह कर्तव्य समझती है कि विकसित क्षेत्रो में सड़कें बनाने के साथ साथ उन क्षेत्रो में भी सड़के बनावे जो कि अविकसित है या पिछडे हुए है ? सरकार ने बतलाया है कि वह इस तरफ ध्यान रखती है, लेकिन जो सड़कें बनायी जा रही है उन से पता चलता है कि इस तरफ ध्यान नही रखा गया है । क्या मै मत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि इसका क्या कारण है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : माननीय सदस्य को शायद याद होगा कि हम ने पाच, छ. या आठ महीने पहले इस सदन मे स्टेट रोड्स के लिए करीब १५ करोड़ रुपये की सहायता करने की बात कही थी और वह सहायता दी गयी, उसके अलावा हम ने यह भी कहा था कि जो सड़कें गांवों को बड़ी सड़कों से मिलाने वाली हैं उनके लिए अगर प्रदेश सरकारें हम से कर्ज लेना चाहें तो उस के लिए साठ लाख रुपया रखा गया है और बाद में उसे बढ़ाने की भी बात कही गयी थी । कुछ प्रदेश सरकारों ने यह सहायता ली और कुछ ने नहीं ली, तो इस में हमारा क्या दोष है ।

Burma Rice

*299. **Shri Assar:** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether it is a fact that monsoon quota of Burma Rice is not supplied before the monsoon to Bombay State; and

(b) if so, how and what arrangement will be made in connection with the ensuing monsoon?

The Minister of Co-operation (Dr. P. S. Deshmukh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Shri Assar: May I know whether instructions have been issued to release stocks of rice in the rural areas?

Dr. P. S. Deshmukh: The distribution is left to the State Government. We have supplied most of the requirements as per the requirements of the State Governments.

Shri B. K. Gaikwad: Do the State Governments inform the Central Government as to how this material is disposed of? My information is that these shops are opened in the cities and not in the villages. So, may I know whether this information has been received by the Central Government from the State Governments?

The Minister of Food and Agriculture (Shri A. P. Jain): This distribution is mostly confined either to the deficit areas or to the urban areas which are normally deficit. It is left to the State Government to find out the proper location for the fair price shops.

Shri B. S. Murthy: What is the total quantity of Burma rice to be yet imported and before what time will it reach India?

Shri A. P. Jain: This supplementary is not very relevant to the main question, nonetheless I shall answer it. The total quantity which was contracted to be imported was 5 lakh tons. Besides that, we are getting a